











# महिला आरक्षण और जातीय जनगणना

जोर पकड़ने लगी है। बिहार सरकार पहले ही जातीय जनगणना का चुनूनी है। अभी उसका खुलासा नहीं हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग की है। इसके पहले भी शिड्डीया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों द्वारा समय-समय पर जातीय जनगणना शुरू करने का दबाव केंद्र सरकार पर बना रहे हैं। महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों से सर्वसमर्पित से पास हो जाने के बाद अब राजनीतिक दलों में जाति जनगणना का सरकार पर दबाव बनाकर चुनौती दी जा रही। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने महिला आरक्षण बिल लाकर महिलाओं के समर्थन पाने के जो सपना देखा था। किसी भी राजनीतिक दल द्वारा उसका विरोध नहीं किया गया। सभी राजनीतिक दलों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए पिछड़ा वर्ग एसटी, एससी और अल्पसंख्यक को आरक्षण देकर्ती की मांग तेज कर दी है। हिंदुत्व की काट के लिए विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण में भी सभी वर्गों की महिलाओं को संसद और विधानसभा में उनकी संख्या के आधार पर अनुपातिक स्थान मिले। इसकी नई लड़ाक राजनीतिक दलों में शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने संसद के अंदर भारत के 90 कैबिनेट सचिवों में से मात्र 3 सचिव पिछड़ा वर्ग के होने के बात कहकर पिछड़ा वर्ग का जो उत्पीड़न हो रहा है। इस पर सारे देश का ध्यान आकर्षित करते हुए पिछड़े वर्ग का समर्थन पाने की लड़ाई तेज कर दी है। पंचायती राज अधिनियम में जिस तरह से महिलाओं के वर्ग बार आरक्षण दिया गया है। इसी तरह का आरक्षण त्वरित रूप से लागू करने की मांग को लेकर सरकार और भाजपा पर दबाव बनाया जा रहा है। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद सभी राजनीतिक दलों की महिलाओं में एक नई स्फूर्ति देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी में भी पिछड़े वर्ग के नेता और कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी महिला आरक्षण में पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने की मांग तेज कर दी है। मध्य प्रदेश ने पिछड़े वर्ग की आबादी 50 फीसदी बढ़ाई जा रही है। इसको ध्यान रखते हुए उन्होंने पृथक बुद्धिमत्ता राज्य की मांग करके अपनी ही पार्टी के ऊपर भारी दबाव बना दिया है। उमा भारती ने 50 फीसदी टिक्की पिछड़े वर्ग को देने की मांग कर भाजपा नेतृत्व के लिये परेशानी बढ़ा दी है।

# विशिष्टता का जहर

डा. रवीन्द्र अरजरिया

और परम सत्ता को साकिया है किन्तु सम्पदा

आर कट्टूता के प्रदेशन न वास्तविक धम आर धम गुरुआ के चन्ना वामयनों का हशिये पर पहुंचना शुरू कर दिया है। कहीं हिन्दू राष्ट्र के मांग उठ रही है तो कहीं इस्लाम की परम्पराओं को थोपने का षडयंत्र चल रहा है। कहीं खालिस्तान की बकालत करने वाले खूनी जंग छेड़ने की धोषणाएं कर रहे हैं तो कहीं पाश्चात्मिशन का साम्राज्य स्थापित करने के प्रयास हो रहे हैं। जीवन पद्धति को प्रभावित करने वाले कारकों को निजता से खींचकर सामूहिकता की दहलीज पर पहुंचा दिया गया है। अजान की आवाज पर इबात में भागने वालों को शख और घटने देने लगा है। गुरुवाणी के स्वरों पर प्रथाना की आपत्ति दज होने लगी है। इन सब के पीछे चन्द षडयंत्रकारियों की बोहरकतें उत्तरदायी हीं जैविदेशी आकाओं के इशारे पर राष्ट्रीय एकता, अखबाड़ता और संप्रभुता को नस्तनाबूत करने में लगी है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि समान जीवनशैली अंगीकार करने वालों के मध्य भी ऊंच-नीच की व्यवस्था कंजम, मान्यताओं, अर्थिक स्थिति, सामाजिक रुतवा, लोकप्रियता जैसी कारकों से आधार पर प्रभावित करना कहां तक उचित है। आस्था वैश्वसी के नेत्रों में विशेष दानदाताओं, राजनीतिक औहदारों, अधिकारियों आदि के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। आम आवाम को दोयथा विकिये जाने लगे हैं। परमात्मा के द्वाजे भी भेदभाव के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोले और बंधनों के बाद लक्ष्य तक पहुंचने पर कुछ क्षणों के लिए ही ही आराध्य को निहारने का मौका दिया जाता है जबकि विशेष प्रबन्धनों के साथ लाव लश्कर लेकर पहुंचने वाले विशिष्टजनों की आवधारणा आस्था के केन्द्र का पूरा तंत्र ही हाथ बांधे खड़ा हो जाता है। परमात्मा के द्वाजे भी भेदभाव के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोले और बंधनों के बाद लक्ष्य तक पहुंचने वाले आस्थावानों को भीड़ का हिस्सा बनाकर धक्का देने वाला तत्र ही विशिष्ट व्यक्तियों के सामने गुलाम बनकर उधार के पैसों से आस्था से जुड़ी मान्यताओं को पूरा करने हेतु पहुंचे मेहनतकश को दिये जाने वाले धक्के निश्चय ही वहां मौजूद परम तत्व को निश्चय ही स्वीकार नहीं होगें। पक्षपात करने वाली व्यवस्था को अनेक आस्था स्थलों ने अपने संस्कृतिधर्म में भी शामिल कर लिया है ताकि संस्था के निजी संविधानों

# ओबीसी के नाम पर बेवकूफ बनाने का ड्रामा

काट दिया गया हा। इन दो नफरतों के कारण जल्दी हो समाप्त हो पुका हा। बहतर ह आप आरक्षण के महत्व को समझें। उसके नाम पर खुद को मुख्याधारा से अलग न करें। अपने भीतर जातिगत नफरत को मिटाइये। थोड़ी कोशिश करेंगे तो इस नफरत से मुक्ति मिल जाएगी। आप अच्छा महसूस करेंगे। सभी समाज के लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि आरक्षण के कारण अवसर खत्म नहीं होते हैं। अवसर खत्म होते हैं दूसरी नीतियों के कारण। घार पूँजीपतियों की पूँजी बढ़ती हो इसके लिए आर्थिक नीतियों का जाल बिछाने के कारण अवसर समाप्त होते हैं। लोग यह समझ नहीं पाते हैं कि उनकी नौकरी में लकावना आरक्षण नहीं है। अवसर की कमी है। सरकार की गूर्हतापूर्ण हककों के कारण अवसर समाप्त हो चुके हैं प्राइवेट हों या सरकारी थेट्र में। ये आरक्षण के कारण नहीं हुआ है। यूँकि आप आर्थिक जगत के मुरिकों खेल को नहीं समझ पाते तो फिर से आरक्षण पर पहुँच जाते हैं कि इसकी वजह से नौकरी नहीं मिल रही है।



डा. सत्यवान सारम  
लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं।

U

सख्ति मांचे आरक्षण के कारण नहा हुआ है। चौंकी आप अर्थिक जगत के मुश्किल खेल को नहीं समझ पाते तो फिर से आरक्षण पर पहुंच जाते हैं कि इसकी बजह से नौकरी नहीं मिल रही है। जबकि जिन्हें आरक्षण मिला है उन्हें भी नौकरी नहीं मिल रही है। अब आते हैं ओबीसी पर। केवल केंद्र सरकार के संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों को जोड़ लें तो पाता चलेगा कि ओबीसी के चालीस से साठ फीसदी तक पद खाली हैं। ओबीसी कोटे की 16000 मेडिकल सीटों का चले जाना किसी अपराध से कम नहीं है। यूजीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में मात्र 09 ओबीसी प्रोफेसर पद रहे हैं जबकि स्वीकृत पद 304 हवं तो ओबीसी को भी वाजिब हक नहीं मिल रहा है। ओबीसी नेता के राज में ओबीसी को भी नौकरी नहीं मिल रही है। वर्ना केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कई हजार ओबीसी के नौजवान लेकर बन गए होते। किंतु बड़ा सामाजिक बदलाव होता। इन पदों पर

का भा लाभ मिलता। अरक्षण के अभिप्राय भी प्रतिनिधित्व से ही है यह प्रतिनिधित्व धीर-धीर महिला अनुसुचित जननाति एवं अन्य पिछले वर्ग एवं दिव्यांग और हाल में अविद्या रूप से पिछड़े समाज के लिए ४८ किया गया है। अब आरक्षण तो लाहो गया लेकिन उसे जमीन पर लानी की जिमेदारी जिन कंठों पर थी, सभी जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त गैर-समता में विश्वास करने वाले थे यही कारण है कि आज भी चतुर्थी श्रेणी को छोड़ कर्ही पर भी आरक्षण वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। क्या उपर्युक्त पद के लिए आरक्षण वर्ग के कैडिडेट नहीं मिलते अथवा मानसिक बीमारी के कारण इस वर्ग का समावेशन नहीं किया जा सकता है?

पिछले कई वर्षों में देश भर के केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों में ओबीसी आक्षित वर्ग की सीटों को नहीं भरा गया। देश के कई विश्वविद्यालय तो अधिकरत पदों पर यह लिख दिया गया कि हमें ओबीसी आरक्षण वर्ग कोई भी उपर्युक्त अव्यर्थी नहीं मिलता।

ताक बाद म इनका समान्य वर्ग है कि किस सोच के साथ उपर्याही-लिख कर आरक्षित वर्ग कमत्र बताने का प्रयास किया गया अप देखेंगे तो पाएंगे कि देश भर संस्थानों में ओबीसी के लोगों के सभी में यही हाल है। औबीसी अधिकार सीटों पर एनएफएस (एनएफएस) भी उपर्युक्त अभ्यर्थी नहीं मिल लगा दिया है। आज एनएफएस लेकर देश भर के आरक्षित वर्ग काफी रोप है। अब सवाल यह उठता है कि पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों को एनएफएस किया जाना, जो लोगों की जातिवादी मानसिकता परिचायक तो नहीं है। क्या ये अपने विवेक का इस्तेमाल बैंडमान लिए करते हैं। अगर ऐसा ही चाहा तो ये समस्या एक दिन विकल्प बन जाएँगी।

आंकड़ों का अध्यन करें हम पाएंगे कि देश के कुल के विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा गामिल होकर समाज में केवल 5 उपर्युक्तपति है। ३

तन है। दरा कंक्रियावाले वाले में प्रोफेसर की तय सीटों की मात्रा प्रतिशत ही भरी गई है। अमूल्य स्थिति एसोसिएट और ऑर्डर प्रोफेसर में भी है। सीटों पर रहने के साथ-साथ ओबीसी वेटिंग क्रीमीलेयर का घटिया खेल उनको कहीं का भी नहीं छोड़ा है जिसका बजह से उनका जर्सर्टिफिकेट तक छिना जा रहा है।

छह या आठ लाख की सीमा से ओबीसी का काह आने वाली पीढ़ियों को पंगु जा रहा है जबकि अन्य अवर्गों में न तो कोई क्रीमीलेयर कोई और बाध्यता? जिसका से इन वर्गों के बड़े-बड़े अफवाह बच्चे भी पीढ़ियों तक आरक्षणीय फायदा उठा पाएंगे। देखें तो ४ कुल आबादी का सबसे बड़ा ओबीसी आरक्षित वर्ग से ३ लेकिन इसी वर्ग की हालत को अच्छी नहीं दिखती। जिस तरह प्रतिष्ठित संस्थानों में जाति के पर योग्य और अयोग्य होने के

द्वालया  
त्र० 4.5  
न यही सेस्टर्टे ट  
खाली  
के साथ  
वेलकर  
जा रहा  
कित का  
है।  
मामूली  
पारकर  
बनाया  
आरक्षित  
र है न  
वजह  
सरों के  
गण का  
पारत में  
हिस्सा  
माता है  
ई खास  
गरह से  
आधार  
ग खेल

हालाक, आवास अभ्यायों के साथ किया गया यह धोखा कोई नया नहीं है। गत वर्ष यानी 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने एक लिखित जबाब में देश के उच्च सदन राज्य सभा को बताया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 880 प्रोफेसरों के पद सहित 3,669 आरक्षित श्रेणी के शिक्षण पद परिक्रम हैं। इसमें 1,711 पद ओबीसी के के रिक्त हैं। संविधान में दिए गए अधिकारों के लिए जब देश के एक बड़े समाज को लड़ा पड़ेगा तो ऐसे में भारत कैसे मजबूत राष्ट्र बनेगा सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास होना भी जरूरी है। देश में हिस्सेदारी के सवाल पर देश के बड़े वर्ग के भीतर निःसंदेह कुछ बेचैनी और अस्तोष है, जिसका समाधान सरकार के पास ही है। बड़े समाज को पीछे छोड़ हम अपने देश को सशक्त नहीं कर सकते। क्या यह कहना उपयुक्त नहीं है कि सारे तथ्यों को जानते हुए भी सरकारों द्वारा ओबीसी वर्ग के साथ धोखा किया जा रहा है?

दलित वोट बैंक मौजूद है। इसी के चलते बसपा से सब हाथ मिलाना चाहते हैं, तो मायावती को भी अपनी इस ताकत पर गुमान है, जिसके चलते वह फूंक-फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही हैं, तो बसपा से हाथ मिलाने को दर्शक नजर आ जाएगी और आईएनडी भारी गढ़बंधन भी कठ्ठ बोलने को तैयार

हाथी नलान का इच्छुक नहीं जो रहा इनडाइरेक्ट और आइएनडीजे इन गठबंधन ना खुछ बातें का रखा। नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों गठबंधन के नेताओं ने हार मान ली हो। सूत्र बताते हैं कि गुपचुप तरीके से मायावती को अपने खेमे में लाने के लिए दोनों गठबंधन दलों के आकाओं द्वारा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के भाजपा और कांग्रेस गठबंधन से दूरी बनाकर चलने वे चलते आईएनडीआईए गठबंधन को यूपी में लोकसभा की 80 सीटों पर करारा झटका लग सकता है।



**सुदेश कुमार**



पार्टी नी है। पार्टी भी लिए दोनों गठबंधन दलों के आकाओं द्वारा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही इसीलिए इस बार मायावी जोड़ने की कोशिश की उ बसपा को साथ लाने की

11

नहा ह जिसके चलत रजनात  
गलियारो में हडकम्प मचा हुआ  
वैसे तो घिले दो दशकों में बस  
लगातार कमजोर हुई है, लेकिन अभी  
भी उसके पास 14 फीसदी दलि  
वोट बैंक मौजूद है। इसी के चलत  
बसपा से सब हाथ मिलान चाहता  
है, तो मायावती को भी अपनी ता  
ताक या गुमान है, जिसके चलत  
वह फूंक-फूंक कर कदम आगे बढ़ा  
रही है, तो बसपा से हाथ मिलाने  
इच्छुक नजर आ रहा एनडीए 3  
आईनडीआईए गठबंधन भी कुल  
बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन  
इसका यह मतलब नहीं है कि दो  
गठबंधन के नेताओं ने हार मान  
हो। सूत्र बताते हैं कि गुपचुप तरीके से  
मायावती को अपने खेमे में लाने

के बहुजन समाज पाठा का सुप्राप्ति मायावती के भाजपा और कांग्रेस गठबंधन से दूरी बनाकर लड़ने के चलते आईएनडीआईए गठबंधन को यूपी में लोकसभा की 80 सीटों पर करारा झटका लग सकता है। ऐसे में आईएनडीआईए एक बार फिर मायावती पर डोरे डालने में लग गया है। बसपा नेत्री मायावती से युपचुप तरीके से बातचीत की जा रही है क्योंकि चुनाव जीतने के लिए इंडिया गठबंधन यूपी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है।

बताते चले कि बसपा के बिना सपा-कांग्रेस एक साथ मिलकर 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ के देख चुके हैं जिसका काई फायदा इन दोनों दलों को नहीं हुआ था

कांग्रेस आर बसपा के शासन नताउने के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। अभी तक यह बातचीत अपने मुकाम तक तो नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन तब से दोनों बीच संवाद बना हुआ है। इसमें गांधी परिवार और उसके करीबी शमिल हैं। राजनीतिक सत्रों के मुताबिक पिछले महीने कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती दोनों बीच गठबंधन को लेकर गुरुत रूप चर्चा भी हो चुकी है। बसपा की ओर से उसके एक पूर्व सांसद की भी इन बातचीत में अहम भूमिका है।

गैरतरलब है कि उत्तर प्रदेश वे विधानसभा चुनाव से पहले बसपा कांग्रेस की गठबंधन की कोशिश परवान नहीं चढ़ पाई थीं। तब त

एसा पारस्परितया प्रदानों ही दलों को बढ़ाव पड़े। चुनाव के बाद सार्वजनिक रूप से बहम बसपा को अपनी में विधानसभा चुनाव थे, पर वह तैयार नहीं हो गया। लोकसभा चुनाव का आधिकारिक रूप की रैणनीति है। टूस की भी जा रहा है कि कठबंधन में बसपा सहज रहेगी, इसका है, लेकिन कांग्रेस में बसपा को साथ रुचि ले रहा है। इसके बसपा के पास अभी दलित बोट बैंक है।

कर दा गंड कि  
म पीछे खींचने  
हाहुल गांधी ने  
हा भी था कि  
रखकर यूपी  
लड़ना चाहते  
हुइ। इस बार  
एन पहले ही  
घोषणा करने  
तरफ कहा यह  
आईएनडीआई  
अन्त में सपा  
वाव मुश्किल  
नेतृत्व, यूपी  
गाने में ज्यादा  
वजह है कि  
गी 14 फीसदी  
ग्रिंस के प्रदेश  
दखा जा रहा ह।

बताया जा रहा है कि अजय राय ने  
यह बयान हाइकमान से इशारा मिलने  
के बाद ही दिया था। संभावना जारी  
जा रही है कि जैसे-जैसे कांग्रेस की  
बसपा के साथ बात आगे बढ़ती  
जाएगी, वैसे-वैसे इस तरह के और  
बयान भी आ सकते हैं। गांधी परिवार  
के नजदीकी नेता के मुताबिक वर्ष  
2017 के विधानसभा चुनाव में सपा  
के साथ कांग्रेस के अनुभव अच्छे  
नहीं रहे। उस चुनाव में कांग्रेस को  
ज्यादा सीटें देने की बात सपा अध्यक्ष  
अखिलेश यादव लगातार कहते रहे,  
लेकिन 145 सीट देने के बाद के  
बावजूद कांग्रेस को 105 सीटें दी  
गई। इसमें से करीब 10 सीटों पर सपा  
ने अपने प्रत्याशी को पंजे पर चुनाव  
ह, उससे बसपा अपर हड म नजर  
आ रही है। बसपा यदि कांग्रेस-सपा  
गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है तो  
वह अपनी मर्जी वाली सीटों पर  
चुनाव लड़ेगी और ऐसी सीटों की  
संख्या भी अधिक होगी। बसपा 20  
से 25 सीटों तक के लिए अपनी  
दावेदारी पेश कर सकती है। बसपा  
की दावेदारी को ना करना सपा,  
कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा।  
अगर वह बसपा को उसकी इच्छा के  
अनुसार सीट नहीं देती है तो बसपा  
के बगैर चुनाव लड़ने पर सपा  
कांग्रेस गठबंधन को बड़ा नुकसान  
उठाना पड़ सकता है। वहीं बसपा  
यदि भाजपा के साथ चली गई तो  
आईएनडीआई के लिए लड़ाई और  
भी मुश्किल हो सकती है।

महिलाओं को मिलेगा यह भी पता नहीं है। और कैसे मिलेगा यह भी स्पष्ट नहीं। नारी शक्ति बन्दन अधिनियम के नाम से आरक्षण के लिए अनुच्छेद 334ए जोड़ा गया है। जिसमें कहा गया है महिला आरक्षण के लिए परिसीमन अनिवार्य भी 33 प्रतिशत क्यों, 50 प्रतिशत क्यों नहीं? और यदि वास्तव में सरकार की नीति महिला आरक्षण अधिनियम को नये भवन में महिला आरक्षण के रूप में पहला विधेयक पेश किया गया और उसे ऐतिहासिक समर्थन के साथ पूरा

परित हुये इस अधिनियम में संविधान के 128 वें संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। हालांकि इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव व 2024 में प्रस्तावित लोकसभा के आम चुनाव में महिला आरक्षण लागू होना असंभव है। क्योंकि महिला आरक्षण के ड्राफ्ट के अनुसार इस कानून के बनने के बाद होने वाली पहली जनगणना और फिर सीटों के परिसीमन के बाद ही महिलाओं हेतु आरक्षित सीटों का निर्धारण किया जायेगा। जबकि 2010 में यू.ए पी ए के शासनकाल में राज्यसभा में महिला आरक्षण सम्बन्धी जो पिछला विधेयक पारित हुआ था उसमें परिसीमन की शर्त नहीं थी। और भाजपा ने भी उस समय परिसीमन जैसी शर्त के बिना ही उस विधेयक का समर्थन किया था। सबाल यह है कि आज जब भाजपा सरकार महिला आरक्षण को लागू करने के लिए अधिनियम बना रही है तो उसे सबसे पहले परिसीमन से होगा? माना जा रहा है कि परिसीमन का कामकसद लोकसभा सीटें बढ़ाना नहीं हो सकता है। गैरतलब है कि 2024 में होने वाली जनगणना भी अभी तक नहीं हुई है। यदि सब कुछ निर्बाध रूप से और बिना किसी टाल मटोल के हुआ तो शायद महिला आरक्षण 2026 वाला लागू हो सके अन्यथा अनिश्चितता व सूरत बनी रहेगी। हालांकि सरकार यह जर्सर बता दिया है कि नरी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने से लोकसभा में महिलाओं की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। यह भी बताया गया है कि 15 वर्ष के लिए आरक्षण व प्रावधान है हालांकि संसद को इस बढ़ाने का अधिकार होगा।

बहरहाल महिला आरक्षण विधेयक परित होने के बाद अनेक विशेषकों राजनीतिज्ञों की तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं। कांग्रेस चाहती है कि इस तत्काल लागू किया जाये। इसे लागू करने के लिए जनगणना या परिसीमन की कोई जरूरत नहीं है। जबकि कुछ

लेकर साफ है तो परिसीमन व जनगणना जैसे बहानों की जरूरत क्या? जिस तरह भाजपा द्वारा दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में महिलाओं को इकट्ठा कर बाकायदा जश्न मनाकर प्रधानमंत्री का महिला अरक्षण अधिनियम के लिये पार्टी की महिलाओं द्वारा धन्यवाद किया गया और उर्हे महिलाओं का इस सदी का सबसे बड़ा नायक व इतिहास पुरुष बताने की कोशिश की गयी उससे कम से कम एक बात तो स्पष्ट है कि बाबजूद इसके कि आगामी विधानसभा व लोकसभा किन्हीं भी चुनावों में महिला उम्मीदवारों के लिए इस आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा परन्तु इसके बाबजूद यह भी तय है कि महिला आरक्षण का यह मुद्दा निकट भविष्य के सभी चुनावों में मुख्य मुद्दा बनने वाला है। इस इसलिये जरूर सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है कि सरकार ने आधी आबादी के प्रति अपनी हमदर्दी का संदेश भी दे दिया और पुरुषों का वर्चस्व भी फिलहाल यथावत बना बहुमत से पारित भी करा लिया गया इससे बेशक यह संकेत तो मिलता है कि सरकार आधी आबादी की हित चिंतक है। परन्तु इन सवालों से भी यही सरकार कैसे बच सकती है कि जब इसी वर्ष 28 मई को नये संसद भवन का उद्घाटन किया गया था उस समय देश की महिला राष्ट्रपति को इस भवन के उद्घाटन हेतु क्यों आमंत्रित नहीं किया गया था? जबकि वह उनका अधिकारी भी था और यदि वे उद्घाटन करतीं तो राष्ट्रपति के महिला होने के नाते आज अच्छा सन्देश भी जाता? और जब बात नये संसद भवन के उद्घाटन की होती है तो उस दिन को देश इसलिये भी नहीं भूल सकता क्योंकि उसी दिन विश्व में देश का नाम रोशन करने वाली महिलाओं ने जो एक भाजपा संसद द्वारा उनका यौन शोषण किये जाने के चलते जंतर मंतर पर धरना दे रही थीं उर्होंने उसी 28 मई को नये संसद भवन के सामने महिला पंचायत आहूत की थी जिसे सरकार ने बलपूर्वक होने नहीं स्थित बयान करने की कोशिश की वर्हीं वे यह बताने से भी नहीं चूर्कीं कि महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण का आरोपी भाजपा संसद इस समय भी लोक सभा में मौजूद है। तृणमूल कांग्रेस संसद काकोली घोष दस्तीदार ने भी याद दिलाया कि देश के लिये स्वर्ण पदक लेने वाली महिलाओं धरने पर थीं जबकि उनका शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी आज संसद में बैठता है? इसी विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सांसदों ने मणिपुर में महिलाओं को नान धुमाये जाने, महिलाओं के प्रति होने रहे राष्ट्रव्यापी अपराध, देश में बढ़ती जा रही बलात्कार की घटनाओं का भी जिक्र किया। बहरहाल सत्ता और विपक्ष खासकर भाजपा व कांग्रेस के बीच महिला आरक्षण का श्रेय लेने की बातें तब तक बेमानी और महिलाओं को भ्रमित करने वाली हैं जब तक यह लागू नहीं हो जाता। इस अधिनियम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसा लोकलुभावन नाम दिया जाना भी तो











## संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ में महिलाएं चला रहीं  
अनोखा बैंक, यहाँ पैसे नहीं मिलते  
हैं बर्तन, आमदनी भी जबर्दस्त



रायपुर, एजेंसी। बैंक शब्द का नाम लेते ही रुपए पैसे की लेनदेन वाले बैंक या ब्लड बैंक याद आ जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में महिलाएं एक अनोखा बैंक चला रही है जहाँ रुपए पैसे या ब्लड नहीं बटिक बर्तन मिलते हैं। देश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत लाग्या 1560 एस बर्तन बैंक चल रहे हैं। इन बैंकों से आम लोग चिन्ह आया जाने, समाझह और पार्टी के लिए बर्तन किरण पर लेते हैं। शहरों में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिवध के बाद इन बैंकों को आम नाचोंकों को प्लास्टिक से बने डिस्पोजेबल आईटम जैसे- थाली, ट्लेट, कटोरी, गिलास एवं चम्मच आदि के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इन्हाँने यही नहीं बर्तन बैंकों से शहरी गरीब महिलाओं को स्वच्छता और क्षमता दी है। इन बैंकों को महिलाओं के लिए अतिरिक्त आमदनी के स्रोत विकसित करने के लिए इसलिए उन्होंने शिकायत के जरिए अपने बैंक की छिपानी की कोशिश की, जिससे उनकी मंथा का पता चलता है।

## प्रयागराज से अगवा व्यापारी के बेटे की बेरहमी से हत्या, अरवारी जंगल में मिला शव

प्रयागराज, एजेंसी। प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ कस्बे से व्यापारी के बेटे को अगवा कर बदमाशों ने चिक्कूट के अवधारी जंगल में पथरों से बरी रहने का मार डाला। इसके बाद शव को जंगल में फेंक कर हत्यारों ने भी स्वागत कर दिया। चरवाहों की सूचना पर रखिवार को सुहू बरगढ़ पुलिस ने जगल से शब्द रखी तो एक दूसरी बैठक आयी। इसके बाद फिर धूलौकर नहीं पूछा तो परिजनों ने खोजीने शुरू की। बताते हैं कि रात करीब साढ़े आठ बजे किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रयागराज को पीछे कर अपहरण की बात करकर पिछोती मारी। कहा कि उसका बेटा शुभ उनके कर्जे में है। पंद्रह लाख रुपये लेकर डॉमारों के जंगल में आने की बात कही। अकालीय की पुलिस का बताया तो उन्होंने को खोजा और खोजने की मात्रा में भी पिछा किया है। इससे शहरों में खुली गाई रुक्मिणी की बात होती है। लेकिन बैठक की 14 वर्षीय बेटा शुभ के परिजनों ने जिला नगर योगिनी मिलने पर मुक्त के परिणम मैं पर पहुंच गया है। प्रयागराज व चिक्कूट की पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ सदर बाजार निवासी पुरुषों ने जैसा करना की चाहत थी। तो उन्होंने जीर्ण बेरहमी के लिए बर्तन बैंक से बर्तन किया है। यह जन भागीदारी द्वारा चलता है। अधिकतर पार्टी या समाजों में बहुतायत उपयोग होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक व्यापार के बैंकों ने एक ऐसे ही बर्तन बैंक के सचालन से में 3 लाख 75 हजार रुपये की आमदनी ढूँढ़ी है। लालिया, दीदी बर्तन बैंक अध्यक्ष, अंबियुक बैंक के लिए अतिरिक्त आमदनी के स्रोत विकसित करने के लिए इसलिए उन्होंने शिकायत के जरिए अपने बैंक की छिपानी की कोशिश की, जिससे उनकी मंथा का पता चलता है।

## नेपाल से इंडिया आने को विदेशी पर्यटकों के लिए नहीं खुले दरवाजे

Indo-Nepal Border

पिथौरागढ़, एजेंसी। कोरोना के बाद नेपाल से आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए भारत ने अब तक दरवाजे नहीं खोले हैं। उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़ और चम्पावत के सीमावर्ती क्षेत्रों में इससे पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ है। साल 2019 तक विदेशी बेरोकटोक भारत प्रवेश करते थे और इनके साथ खूब विदेशी मुद्रा भी आती थी। कोरोना से पहले धाराखुला से लेकर बनबसा तक हर शाल औसतन 7 हजार से अधिक विदेशी पर्यटक नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करते थे। संक्रमण के दौरान भारत ने विदेशियों के साथ साथ पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ है। लेकिन विदेशीयों का आवासीन नहीं बदला रहा है। नेपाल के एक दूसरे देश से देश से जुड़ा है। नेपाल के बारे में विदेशीयों की जानकारी भी बदला रही है। जिससे पुलिस व्यापारी की बात आयी।

पिथौरागढ़, एजेंसी। कोरोना के बाद नेपाल से आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए भारत ने अब तक दरवाजे नहीं खोले हैं। उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़ और चम्पावत के सीमावर्ती क्षेत्रों में इससे पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ है। साल 2019 तक विदेशी बेरोकटोक भारत प्रवेश करते थे और इनके साथ खूब विदेशी मुद्रा भी आती थी। कोरोना से पहले धाराखुला से लेकर बनबसा तक हर शाल औसतन 7 हजार से अधिक विदेशी पर्यटक नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करते थे। संक्रमण के दौरान भारत ने विदेशियों के साथ साथ पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ है। लेकिन विदेशीयों का आवासीन नहीं बदला रहा है। नेपाल के एक दूसरे देश से देश से जुड़ा है। नेपाल के बारे में विदेशीयों की जानकारी भी बदला रही है। जिससे पुलिस व्यापारी की बात आयी।

## जब भी मौका मिला महिला पहलवानों से छेड़छाड़ करते थे बृजभूषण, कोर्ट में दिल्ली पुलिस की दलील

नई दिल्ली, एजेंसी।

महिला पहलवानों के यैन शोयांग मालिनी में शनिवार को दिल्ली पुलिस ने अदालत में अपनी दस्तील पैश करते हुए कहा कि भारतीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बिलाफ जो साया और सबूत मिले हैं, वह आपेत तय करने के लिए पाये हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि बृजभूषण सिंह को जब भी मौका मिलता था, वह महिला पहलवानों की लज्जा भग करने की कोशिश करता था।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने महिला पहलवानों के यैन शोयांग मालिनी में दिल्ली पुलिस की दस्तील में दिल्ली पुलिस की दस्तील से बृजभूषण शरण सिंह को पता था कि वह बया कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने शिकायत के जरिए अपने बैंक की छिपानी की कोशिश की। जिससे उनकी मंथा का पता चलता है।

दिल्ली पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र पर बहस करते हुए कहा कि बृजभूषण शरण सिंह को पता था कि वह बया कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने शिकायत के जरिए अतिरिक्त आमदनी के स्रोत विकसित करने के लिए उन्होंने बैंक व्यापार के लिए बर्तन बैंक के लिए पाया था। यह जन भागीदारी द्वारा चलता है।

पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र पर बहस करते हुए कहा कि तजाकिस्तान का वर्तन करते हुए कहा कि बृजभूषण शरण सिंह को पता था कि वह बया कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने बैंक व्यापार के लिए बर्तन बैंक के लिए पाया था। यह जन भागीदारी द्वारा चलता है।

पुलिस ने अदालत का वर्तन करते हुए कहा कि तजाकिस्तान में एक इंवेट के दैनिक बैंक व्यापार के लिए बर्तन बैंक के लिए पाया था। यह जन भागीदारी द्वारा चलता है।



नहीं। मसला यह है कि उनके साथ गलत किया गया। दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ताओं के साथ दिल्ली में डल्लूफूर आई के कार्यालय में हुई घटना का निकल किया और कहा कि बृजभूषण को पता था वह बया कर रहे हैं।

कमरे में बुलाया और जबरदस्ती गले लगाया। विशेष करने पर बृजभूषण सिंह को कहा कि पिंडा की तरह व्यवहार किया था। इससे पता चलता है कि बृजभूषण को पता था वह बया कर रहे हैं।

इस पुलिस ने एक महिला पहलवान की शिकायत का वर्तन करते हुए कहा कि तजाकिस्तान में एक इंवेट के दैनिक बैंक व्यापार के लिए बर्तन बैंक के लिए पाया था। यह जन भागीदारी द्वारा चलता है।

पुलिस ने एक महिला पहलवान की शिकायत का वर्तन करते हुए कहा कि तजाकिस्तान में एक इंवेट के दैनिक बैंक व्यापार के लिए बर्तन बैंक के लिए पाया था। यह जन भागीदारी द्वारा चलता है।

पुलिस ने एक महिला पहलवान की शिकायत का वर्तन करते हुए कहा कि तजाकिस्तान में एक इंवेट के दैनिक बैंक व्यापार के लिए बर्तन बैंक के लिए पाया था। यह जन भागीदारी द्वारा चलता है।

पुलिस ने एक महिला पहलवान की शिकायत का वर्तन करते हुए कहा कि तजाकिस्तान में एक इंवेट के दैनिक बैंक व्यापार के लिए बर्तन बैंक के लिए पाया था। यह जन भागीदारी द्वारा चलता है।

पुलिस ने एक महिला पहलवान की शिकायत का वर्तन करते हुए कहा कि तजाकिस्तान में एक इंवेट के दैनिक बैंक व्यापार के लिए बर्तन बैंक के लिए पाया था। यह जन भागीदारी द्वारा चलता है।

पुलिस ने एक महिला पहलवान की शिकायत का वर्तन करते हुए कहा कि तजाकिस्तान में एक इंवेट के दैनिक बैंक व्यापार के लिए बर्तन बैंक के लिए पाया था। यह जन भागीदारी द्वारा चलता है।

पुलिस ने एक महिला पहलवान की शिकायत का वर्तन करते हुए कहा कि तजाकिस्तान में एक इंवेट के दैनिक बैंक व्यापार के लिए बर्तन बैंक के लिए पाया था। यह जन भागीदारी द्वारा चलता है।

पुलिस ने एक महिला पहलवान की शिकायत का वर्तन करते हुए कहा कि तजाकिस्तान में एक इंवेट के दैनिक बैंक व्यापार के लिए बर्तन बैंक के लिए पाया था। यह जन भागीदारी द्वारा चलता है।

पुलिस ने एक महिला पहलवान की शिकायत का वर्तन करते हुए कहा कि तजाकिस्तान में एक इंवेट के दैनिक बैंक व्यापार के लिए बर्तन बैंक के लिए पाया था। यह जन भागीदारी द्वारा चलता है।